Interest shown by Foreign Companies in Solar Photovoltaic Industry

@3018. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some foreign companies have shown an active interest in the Indian Solar Photovoltaic Industry;

(b) if so, what are the details thereof including the names of the foreign companies which have shown interest in this regard;

(c) whether it is also a fact that the licensing norms had been eased recently for manufacturing Solar Photo-voltaic cells by the FERA companies; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Yes, Madam. Foreign companies which have shown interest in the Indian photovoltaic industry in the past include Photowatt of France, BP Solar of U.K., Telefunken Technic of the Federal Republic of Germany, Helios Technology of Italy, Solapac of Canada, and Astropower, Chronar Corporation, Energy conversion Devices and Solec of USA.

(c) and (d) The Statement on Industrial Policy which was laid on the table of the House on July 24, 1991 according to which licensing has been abolished for FERA companies, subject to the conditions stated therein, is also applicable to the solar photovoltaic industry.

@Previously Unstarred Question 2396, transferred from the 12th March, 1992.

Southern States neglected in Generation of Power

3019. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Southern States have been neglected in the power sector for generation of electricity for a long time; and

(b) whether it is also a fact that in the total power production in the country, only 25 per cent installed capacity, is being planned through the southern states are imposing power cuts for various industries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Out of a total capacity of 66066.01 MW in the country as on 31st March, 1991, about 16,675.52 MW (25.24%) is in operation in the Southern Region.

Growth of power sector in a Region depends on various factors such as the extent of industrialisation, investment by the State Governments in power projects, availability of resources and other inputs and demand for power etc. Power to various consumers in the States is regulated by the State Governments on the basis of requirement and availability of energy. The gap in the demand and availability of power is met by the respective States by imposing power cuts and peak period restrictions.

दिल्ली में विद्युत शुल्क की दरें

3020. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री 10 मार्च, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1989 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली में बिजली की प्रति यूनिट कितनी दर प्रभारित की जा रही है; और

(ख) दिल्ली में बिजली की घरेलू खपत और पावर की खपत के लिए प्रति यूनिट दरों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

दिल्ली में विद्युत शुल्क की दरें

उपभोक्ता की श्रेणी	1.3.91 से लागू टैरिफ* प्रति यूनिट (पैसों में)
घरेलू	40 (प्रथम 100 यूनिट) 50 (100 यूनिट के बाद आगामी 100 यूनिटों के लिए) 150 (200 यूनिट के बाद आगामी 100 यूनिट के लिए) 200 (300 यूनिट से अधिक के लिए)
घरेलू (विद्युत)	
अलग से डिलीवरी प्वाइंट	200
गैर घरेलू	
निम्न वोल्टता	150
उच्च वोल्टता	170 - 60 रुपये प्रति के०वी०ए०
जल आपूर्ति	137
औद्योगिक	
लघु उद्योग विद्युत (एस० आई० पी०)	125
वृहत औद्योगिक विद्युत (एल० आई० पी०)	200 - 60 रुपये प्रति के०वी०ए०
सड़क रोशनी (स्ट्रीट लाइटिंग)	137
कृषि	20

*दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाये गये विद्युत शुल्क को छोड़कर।

रिहन्द पन बिजली परियोजना में मध्य प्रदेश का भाग

3021. **श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर**: क्या **विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिहन्द पन बिजली परियोजना द्वारा किये जाने वाले विद्युत उत्पादन में मध्य प्रदेश का भाग 15 प्रतिशत है किन्तु गत अनेक वर्षों से उक्त भाग मध्य प्रदेश को नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को विद्युत उत्पादन में उसका सम्यक भाग दिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने द्वारा उपभोग की गई विद्युत के लिये मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान कर दिया है, और यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) रिहन्द जल विद्युत परियोजना, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की परियोजना है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड तथा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के बीच रिहन्द की विद्युत के बंटवारे के बारे में एक समझौता हुआ है जिसमें यह प्रावधान है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को रिहन्द की विद्युत में से देय हिस्से की विद्युत की आपूर्ति करने में समर्थ नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड सम्मत शर्तों पर इस प्रकार के विद्युत आहरण के लिए प्रतिपूर्ति करेगा। इस मामले का समाधान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज्य सरकारों के बीच द्विपक्षीय आधार पर किया जायेगा।

Bhagavatula Charitable Trust

@3022. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the work of Bhagavatula Charitable Trust (BCT), Vishakhapatnam on and utilisation of wind power;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government are providing full support in this direction for transfer of need-based technology for rural development?

@Previously Unstarred Question 1356, transferred from the 5th March, 1992.